रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी एमक्यू -9 ड्रोन्स को रोका: सीरिया में सुखोई-35 ने फ्लेयर्स दागे; ड्रोन को रास्ता बदलना पड़ा

दमिश्क।
सीरिया में बुधवार को रूस के 3 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के 3 एमक्यू -9 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक, रूस के सिखोई-35 फायटर जेट्स ने ड्रोन्स के सामने पैराशूट से फ्लेयर्स दागने शुरू कर दिए, जिससे उनका फ्रंट व्यू ब्लॉक होने लगा। इसके बाद उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। अमेरिका ने कहा है कि उनके ड्रोन्स सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों की निगरानी कर रहे थे। अमेरिकी वायु सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रिनकेविच ने रूस की इस हरकत को गैर-जिम्मेदाराना और असुरक्षित बताया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने घटना का एक वीडियो भी रिलीज किया है। इसे ड्रोन के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे रूसी फाइटर जेट्स अमेरिका के एमक्यू -9 ड्रोन्स के बेहद पास उड़ान भर रहे हैं। इसी दौरान एक फाइटर जेट ड्रोन के ठीक सामने आकर अपने आफ्टरबर्नर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी स्पीड और प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से ड्रोन ऑपरेटर को उसे उड़ाने में काफी दिक्कत होने लगती है। जनरल ग्रिनकेविच ने कहा- हमारे ड्रोन सुबह करीब 10:40 पर क्षेत्र में एक मिशन के तहत निगरानी कर रहे थे, तभी रूस के लड़ाकू विमान उन्हें परेशान करने लगे। हम रूस से सीरिया में इस तरह की लापरवाही को रोकने की अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में रूस की एयरफोर्स आईएसआईएस को हराने के मिशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करेगी। सीरिया में अमेरिका और रूस दोनों की आर्मी अक्सर ऑपरेशन चलाती रहती हैं। अमेरिका की करीब 900 फोर्सेज सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से लड़ने के लिए कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ काम करने के लिए तैनात हैं। वहीं रूस की सेना सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थन में वहां मौजूद हैं। इससे पहले मार्च में रूस-यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सुखोई फाइटर जेट ने अमेरिका के एडवांस्ड रीपर ड्रोन पर हमला किया था। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन एमक्यू -9 रीपर सर्विलांस कर रहा था। रूस के दो एसयू-27 ने इस रीपर को 40 मिनट तक घेरकर उस पर फ्यूल गिराया था। ये फ्यूल रीपर के प्रोपेलर में पहुंचा और ड्रोन कुछ देर बाद ब्लैक सी में क्रैश हो गया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ गया था। यूएस एयरफोर्स के जनरल जेम्स हैकर ने रूस की हरकत को बेहद गैरजिम्मेदार और भड़काऊ बताया था। उधर, रूस ने अमेरिका के आरोपों से इनकार किया था। उसने कहा था- यह महज एक हादसा है। हम मलबा तलाशने में अमेरिका की मदद करेंगे। इसके लिए हमारे पास अमेरिका और नाटो से ज्यादा बेहतर तकनीक है।

न्यूज ब्रीफ

यूक्रेन बोला- हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने रखे विस्फोटक: काखोवका बांध के बाद इसे भी तबाह करने की प्लानिंग; यूएन करेगा दावों की जांच

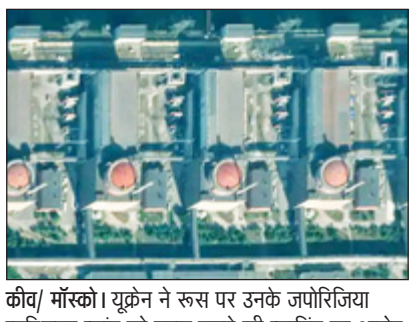

कीव/ मॉस्को। यूक्रेन ने रूस पर उनके जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की प्लानिंग का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने न्यूक्लियर प्लांट की छतों पर माइन्स और विस्फोटक रखे हैं। इन आरोपों के बाद यूएन की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि वो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया की जांच करेगा। इसके लिए आईएईए ने बुधवार को रूस से न्यूक्लियर प्लांट को चेक करने के लिए ज्यादा एक्सेस की मांग की है। रूस ने पहले बांध को तबाह किया अब न्यूक्लियर प्लांट की बारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से कहा है कि रूस ने पिछले महीने हमारे काखोवका बांध को तबाह किया था। अब वो परमाणु प्लांट को तबाह करने की तैयारी कर रहा है। हमले की आशंकाओं के बीच पिछले हफ्ते यूक्रेन ने प्लांट के आसपास के इलाकों में ड्रिल भी की थी। हालांकि, रूस ने जेलेंस्की के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रूस की न्यूक्लियर कंपनी के एडवाइजर रेनात कार्चा ने कहा है कि हमें प्लांट में विस्फोटक रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। टेंशन बढ़ाने के लिए यूक्रेन ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री 5 जुलाई की रात को न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी कर रही थी। इसका इल्जाम वो रूस पर लगाना चाहते थे। आईएईए के अधिकारी ने बताया है कि वो न्यूक्लियर प्लांट की यूनिट 3 और 4 की खास तौर पर जांच करना चाहता है। जपोरिजिया में बने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने जंग शुरू होने के एक महीने बाद ही मार्च 2022 में कब्जा कर लिया था।

मैक्सिको में बस 80 फीट गहरी खाई में गिरी: हादसे में एक साल के बच्चे समेत 29 की मौत,19 घायल; ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खोया

मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका में बुधवार रात एक बस 80 फीट खाई में गिर गई। इस हादसे में एक साल के बच्चे समेत 29 लोगों की जान चली गई। 19 लोग घायल हो गए। बस मैक्सिको सिटी से ओक्साका के योसनडुआ जा रही थी। ओक्साका सरकार के सेक्रेटरी जनरल जीसस रोमेरो लोपेज ने बताया हादसा मगडालेना पेनास्को गांव के पास हुआ। मृतकों में 13 पुरुष, 13 महिलाएं और एक साल का बच्चा शामिल है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जीसस रोमेरो ने बताया कि हादसे की जांच शुरू हो गई है। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे हादसा तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ। अल जजीरा के मुताबिक ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से बस खाई में गिर गई। जहां ये हादसा हुआ वह शहर पहाड़ी इलाके में बसा है। घुमावदार सड़कें हैं और गहरी खाई हैं। सिविल प्रोटेक्शन की रेस्क्यू टीम ने घायलों को नजदीक के गांव में शिफ्ट किया। यहां से घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक, जब घायलों को अस्पताल लगाया गया तो 6 लोग गंभीर रूप से घायल थे और बेहोश थे। बस को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई।

मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को हो सकती है जेल

स्टाकहोम । मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को छह महीने जेल की सजा हो सकती है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग पर स्वीडन में जून में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है। बता दें कि स्वीडन के दक्षिण में स्थित शहर मालमो में बीते जून में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 20 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुईं। जून में मालमो में हुए धरने प्रदर्शन को पर्यावरण संरक्षण संगठन ता तिलबाका फ्रेमटिडेन ने आयोजित किया था। धरने प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मालमो बंदरगाह में प्रवेश के रास्तों को ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। इस दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग समेत अन्य प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन की जगह से चले जाने को कहा लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग समेत अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

इमरान की गिरफ्तारी के लिए ऑर्डिनेंस

राष्ट्रपति हज पर थे, केयर टेकर प्रेसिडेंट ने आधी रात मंजूरी दी; तोशाखाना केस में पेशी

इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए शाहबाज शरीफ सरकार ने एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात केयर टेकर प्रेसिडेंट साजिद संजरानी ने इस पर दस्तखत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतें तक इमरान पर खास मेहरबान हैं। मंगलवार को ही उन्हें एक साथ 16 मामलों में जमानत दी गई थी। इसके बाद सरकार ने खान को घेरने के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के नियमों में बदलाव के लिए ऑर्डिनेंस पास करा लिया। खास बात ये है कि इस दौरान इमरान के कट्टर समर्थक प्रेसिडेंट आरिफ अल्वी परिवार के साथ हज पर गए थे और केयर टेकर प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संजरानी के पास थी, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य हैं। इमरान को तोशाखाना केस में निचली अदालत के सामने पेश होना है।

सरकार की चाल

शाहबाज शरीफ सरकार इमरान को 145 में से सिर्फ एक मामले में गिरफ्तार कर सकी है। 9 मई को उन्हें अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट स्कैम केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खान को बेल दे दी, बल्कि आगे किसी भी केस में उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। 9 मई की गिरफ्तारी के बाद इमरान समर्थकों ने फौज के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। हिंसा में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 259 लोग घायल हुए। खान मरने वालों का आंकड़ा 25 बताते हैं। इस मामले में अब तक 1700 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ज्यादातर का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। बहरहाल, सरकार ने जब यह देख लिया कि अदालतें खान को बचाती रहेंगी तो उसने एनएबी कानून को हथियार बनाया और वो भी तब जबकि उसे पता था कि प्रेसिडेंट अल्वी देश में नहीं हैं। लिहाजा, ऑर्डिनेंस पर केयर टेकर प्रेसिडेंट ही दस्तखत करेंगे। एक और रोचक बात यह है कि प्रेसिडेंट अल्वी का सऊदी अरब का हज दौरा जैसे ही फाइनल हुआ, उसी दिन सरकार ने संसद सत्र स्थगित कर दिया। इसकी वजह यह थी कि संसद सत्र के चलते सरकार ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती थी। इसके लिए बिल लाना पड़ता और फिर इसे पास कराने में कई दिन लगते।

फंसेंगे इमरान

एनएबी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस की ज्यादातर बातें ऐसी हैं, जिनसे साफ नजर आता है कि इसका मकसद इमरान को कानून के शिकंजे में लाना और उन्हें गिरफ्तार करना है। इसके तहत- एनएबी चेयरमैन को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है। इसमें आरोप यह लगाया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। इमरान जब सत्ता में थे तो उन्होंने एनएबी में फिजिकल रिमांड 90 दिन रखी थी। बाद में शाहबाज शरीफ सरकार ने इसे 14 दिन कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत अब 30 दिन का तयशुदा रिमांड रहेगा और एनएबी चेयरमैन इसे कई दिन बढ़ा सकता है। इसके अलावा एनएबी की कस्टडी को किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। बहुत मुमकिन है कि एनएबी की हिरासत में रहते हुए ही 9 मई की हिंसा के मामले में भी इमरान को गिरफ्तार कर लिया जाए। खान और उनकी पत्नी बुशरा को एनएबी कई बार पूछताछ के लिए बुला चुका है। वो हाजिर नहीं होते। अब एनएबी चेयरमैन उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे सकता है। एनएबी ने अल कादिर स्कैम में खान से कुछ पेपर्स भी मांगे थे। उन्होंने कई महीने बाद भी ये नहीं दिए।

सिर्फ एक गवाह काफी

नए ऑर्डिनेंस में एक और नियम पहली बार शामिल किया गया है। इसके मुताबिक, अगर अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में नामजद कोई आरोपी सरकारी गवाह बन जाता है तो उसकी गवाही आखिरी मानी जाएगी। खास बात ये भी है कि इस गवाह को गवाही के पहले एक एफिडेविट पर दस्तखत करने होंगे और फ्यूचर में अगर वो गवाही से मुकरा तो उसके खिलाफ नया केस दर्ज किया जाएगा और इसमें उसे सजा भी होगी। 9 मई की हिंसा के मामले में इमरान के कई करीबी साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं। कई नेता फरार हैं तो ज्यादातर ने पार्टी छोड़ दी है। अब अगर इमरान की पत्नी बुशरा की दोस्त फराह गोगी या फिर जुल्फी बुखारी (तोशाखाना केस में भी आरोपी) या फिर पूर्व रक्षा मंत्री परवेज खटक सरकारी गवाह बनते हैं तो इमरान को न सिर्फ इस मामले में सजा होगी, बल्कि वो पांच साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। उनकी पार्टी पहले ही पूरी तरह बिखर चुकी है। ऐसे में खान का पॉलिटिकल कॅरियर करीब-करीब खत्म हो जाएगा।

अल कादिर ट्रस्ट स्कैम

करीब 4 साल पहले अल कादिर ट्रस्ट का मामला ब्रिटेन से शुरू हुआ। वहां नेशनल क्राइम एजेंसी एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार करती है। जांच के दौरान पता लगता है कि उसके पास करीब 60 अरब रुपए (पाकिस्तानी करेंसी में) हैं।

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गैस लीक, 16 की मौत

इनमें एक साल का बच्चा भी शामिल; अवैध खनन के चलते गैस रिसाव की आशंका

जोहान्सबर्ग।
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की एक बस्ती में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां संदिग्ध गैस लीक से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 5 महिलाएं और तीन बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। गौटेंग प्रान्त के हेड ऑफ गवर्नमेंट पन्याजा लेसुफी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि कौन सी गैस के लीक होने से ये हादसा हुआ। जोहान्सबर्ग के पूर्व में बोक्सबर्ग जिले के पास एंजेलो नाम की एक अवैध बस्ती है। ये इलाका अवैध खनन गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। इमरजेंसी सर्विस एजेंसी के प्रवक्ता विलियम एनटलैडी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घटनास्थल पर 24 लोगों के शव मिले हैं। हालांकि, अधिकारियों ने बाद में 16 लोगों की ही मौत होने की पुष्टि की। वहीं, अस्पताल में भर्ती लोगों में से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। विलियम एनटलैडी के मुताबिक, इमेरजेंसी सर्विस एजेंसी को गैस विस्फोट के बारे में रात करीब 8 बजे एक कॉल मिली। जब वर्कर्स वहां पहुंचने तो उन्हें पता चला कि ये एक सिलेंडर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। वहीं लेसुफी ने बताया कि घटनास्थल पर हर शव बिखरे हुए थे। हादसे में मरने वाले एक बच्चे की उम्र एक साल थी। साउथ अफ्रीका के मीडिया ने इस बात की भी आशंका जताई है कि ये गैस लीक क्षेत्र में हो रही गैर-कानूनी खनन की एक्टीविटीज से भी जुड़ी हो सकती हैं। बोक्सबर्ग जिले के स्थानीय अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा- शुरुआती जांच से पता चला है कि गैस का इस्तेमाल अवैध खनन गतिविधियों के हिस्से के रूप में किया जा रहा था। साउथ अफ्रीका हजारों अवैध खनिकों का घर है। यहां बेरोजगारी दर लगभग 32प्रतिशत है। साउथ अफ्रीका में अवैध खनन को जमा जमास कहते हैं, जिसका मतलब होता है किस्मत आजमाने वाला। साउथ अफ्रीका में हजारों लोग अवैध खनन का काम करते हैं। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का एक कॉमर्शियल एरिया है, जहां 1880 के दशक में सोने की खोज के दौरान खुदाई शुरू की गई थी। जोहान्सबर्ग के एक टाउन में पिछले साल 25 दिसंबर को टैंक विस्फोट हुआ था।

हथियारों की धीमी आपूर्ति के कारण जवाबी हमले में हुई देरी', जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर लगाया आरोप

कीव ।
रूस और यूक्रेन युद्ध को एक साल से भी ज्यादा हो गया है। रूस ने पिछले साल फरवरी में हमला किया था। इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर जवाबी हमले में देरी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम से हथियारों की धीमी आपूर्ति के कारण जवाबी कार्रवाई करने में करीब चार महीने लग गए। यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेसा में जेलेंस्की ने खुलासा किया कि उन्होंने रूस के खिलाफ बहुत पहले जवाबी कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। जवाबी कार्रवाई जून की शुरुआत में शुरू हुई। उन्होंने कहा कि देरी से कार्रवाई करने की वजह से रूस ने कब्जाए शहरों में अपनी मजबूती अच्छी कर ली। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के मैदान में कुछ कठिनाइयों के कारण हमारा जवाबी हमला धीमा हो रहा है। वहां भारी खनन किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि हमारा जवाबी हमला बहुत पहले हो, क्योंकि हर कोई समझता है कि अगर जवाबी हमला बाद में होगा, तो क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खनन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन करने वाले नेताओं और अमेरिका का आभारी हूं। लेकिन सच यह भी है कि मैंने जवाबी हमले से पहले अमेरिका और यूरोपीय नेताओं से कहा था कि आपूर्ति की कमी के कारण अधिक जानें जा सकती हैं। इसलिए

हम अपना जवाबी हमला पहले शुरू करना चाहेंगे और इसके लिए हमें सभी हथियारों और सामग्री की आवश्यकता होगी।

वहीं, इससे पहले यूक्रेन के सैन्य कमांडर-इन-चीफ वालेरी जालुजनी ने पश्चिम से हथियारों को देरी से भेजने पर निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अभी भी अपने सहयोगियों द्वारा वादा किए गए एफ-16 लड़ाकू विमानों का इंतजार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हम रूस से जीतने या हारने के बारे में नहीं बोल रहे। यह केवल बराबर होने के बारे में है। उन्होंने कहा कि एफ-16 को मानवीय समर्थन के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि अगर रूस काला सागर अनाज पहल का विस्तार नहीं करने का फैसला करता है तो यूक्रेन द्वारा शिपिंग कॉरिडोर को खुला रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

पाक सेना 5 महीनों तक नहीं करेगी सैन्य अभ्यास: आर्मी के पास रिजर्व फ्यूल की कमी हुई; 1 किमी में 2 लीटर तेल इस्तेमाल करते हैं पाक के टी-80 टैंक

इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का असर उसकी सेना पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने फ्यूल की कमी होने की वजह से अगले 5 महीने यानी दिसंबर तक कोई भी मिलिट्री ड्रिल नहीं करने का फैसला किया है। मिलिट्री ट्रेनिंग के डायरेक्टर जनरल ने इसे लेकर सभी विभागों को एक लेटर जारी किया है। इसमें सैन्य अभ्यास टालने की मेन वजह रिजर्व फ्यूल की कमी बताई गई है। दरअसल, रिजर्व फ्यूल सेना के रूटीन कामों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ये वॉर रिजर्व से अलग होता है। वॉर रिजर्व जंग लड़ने के लिए सुरक्षित रखा गया फ्यूल होता है।

पाक सैन्य अभ्यास में करता है टी-80 टैंक्स का इस्तेमाल

मिलिट्री एक्सपर्ट और भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल दनवीर सिंह के मुताबिक पाकिस्तान सैन्य अभ्यास के लिए ञ्ज-80 टैंक काफी इस्तेमाल में लाता है। जो प्रति किलोमीटर 2 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सैन्य अभ्यास के लिए सेना को काफी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान की लगातार खराब होती अर्थव्यवस्था के बीच सेना के लिए फ्यूल हासिल करना मुश्किल

होता जा रहा है। जुलाई में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 260 रुपए प्रति लीटर पार कर चुकी हैं।

पाक ने यूक्रेन से खरीदे थे टी-80 टैंक

एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 2,467 बैटल टैंक्स हैं। भारत ने जब रूस के टी-90 टैंक्स खरीदे तो उनके काउंटर के लिए पाकिस्तान ने 1996 में इनका डीजल वर्जन टी-80 यूक्रेन से खरीदा था। टैंक्स की टेस्टिंग के बाद यूक्रेन से ऐसे 320 टैंक्स खरीदे थे। कर्नल दनवीर सिंह के मुताबिक पाकिस्तान ही नहीं भारतीय सेना को भी 1990 के दशक आर्थिक तंगी के चलते में फ्यूल की कमी हुई थी। इससे निपटने के लिए सेना ने 2 साल तक मिलिट्री एक्सर्साइज के लिए बैटल टैंक्स की बजाए ट्रक का इस्तेमाल किया था।

पाक की सेना खाने की कमी की शिकायत कर चुकी

सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना ने साल की शुरुआत में खाने की कमी की भी शिकायत की थी। कई फील्ड कमांडरों ने क्वार्टर मास्टर जनरल को लेटर लिखे थे। पिछले साल पाकिस्तान की आर्मी ने फंड की कमी के चलते अपने सैनिकों को हर शुक्रवार मिलिट्री व्हीकल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। सेना ने अपने कमांडरों से बिजली और गैस का इस्तेमाल कम करने को भी कहा था।

पाक के दिवालिया होने का खतरा टला

पाकिस्तान एक बार फिर दिवालिया होने से बच गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत 3 अरब डॉलर का कर्ज देने का फैसला कर चुका है। आईएमएफ और पाकिस्तान की सरकार के बीच 9 महीने का स्टैंडबाय अरेंजमेंट हुआ है। हालांकि, अभी इसे आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है।

जापान समुद्र में छोड़ेगा 132 करोड़ लीटर रेडियोएक्टिव पानी

यूएन एजेंसी से मिला अप्रूवल; चीन, साउथ कोरिया समेत कई देश कर रहे विरोध

टोक्यो।
जापान बहुत जल्द अपने खराब हो चुके न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद ट्रीटेड रेडियोएक्टिव वॉटर को पैसिफिक ओशन में छोड़ने जा रहा है। इसके लिए उसे यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग से अप्रूवल भी मिल गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रौसी मंगलवार को जापान पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मिलकर सेफ्टी रिव्यू किया। कहा कि रेडियोएक्टिव वॉटर को छोड़ने का जापान का प्लान सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार सही है। हालांकि, जापान में कोस्टल एरिया में रह रहे लोग और चीन समेत कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। 2011 की सुनामी से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का कूलिंग सिस्टम हुआ था ठप पैसिफिक ओशन में 132 करोड़ लीटर पानी छोड़े जाने को लेकर जापान की फिशिंग इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने भी चिंता जताई है। दरअसल, मार्च 2011 में आई सुनामी की वजह से फुकुशिमा के न्यूक्लियर प्लांट का कूलिंग और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ठप हो गया था। गर्मी की वजह से वहां मौजूद तीनों रिएक्टर्स के कोर पिघल गए थे, जिसके चलते काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैला था।

पानी छोड़ने के लिए 1 हफ्ते में मिल सकता है परमिट

न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने के प्लान की घोषणा 2021 में की गई थी। तब कहा गया था कि ये काम अगले 2 सालों में शुरू हो जाएगा। जापान की रेगुलेटरी बॉडी ने 30 जून को ही अपना इंस्पेक्शन पूरा कर लिया था। यूएन की जांच के बाद प्लांट की देखभाल कर रही कंपनी टेपको को एक हफ्ते के अंदर पानी छोड़ने का परमिट मिल

सकता है।

इसके बाद वो कभी भी पानी रिलीज करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कोई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। पानी को ओशन में डिस्चार्ज करने में कई दशकों का समय लगेगा। इसे 1 किलोमीटर के पाइप के जरिए छोड़ा जाएगा।

1 हजार टैंक में स्टोर है न्यूक्लियर प्लांट का पानी

इस न्यूक्लियर प्लांट को मेनटेन करने वाली कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर ने बताया कि प्लांट में मौजूद पानी के ट्रीटमेंट के बाद उसे एक हजार टैंकों में स्टोर किया गया है। इस पानी की क्वांटिटी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 500 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी है। इस पानी को वहां से हटाए जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट किया जा सके। जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पानी को महासागर में छोड़ने से पहले साफ कर दिया गया है। हालांकि, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अभी भी ट्रीटियम के कण हैं। ट्राइटियम एक रेडियोएक्टिव मैटीरियल है, जिसे पानी से अलग करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे तो इससे कॉन्टैक्ट में आने पर ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर ये किसी के शरीर में काफी बड़ी मात्रा में चला जाए तो इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जापान में न्यूक्लियर प्लांट का पानी और वेस्ट मैटिरियल काफी सालों से परेशानी बना हुआ है। पानी को पैसिफिक महासागर में छोड़े जाने का साउथ कोरिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया विरोध जता चुके हैं। वहीं जापान लगातार इस बात का आश्वासन देता रहा है कि वो इंटरनेशनल मानकों के आधार पर ट्रीटियम की मात्रा को कम करने के बाद ही पानी को डिस्चार्ज करेगा। जापान के पैसिफिक सी में इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट का पानी छोड़ने से डरने की वजह जायज है। 1940 के दशक में साउथ पैसिफिक में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने एक के बाद एक कई न्यूक्लियर टेस्ट किए थे।